आवश्यकता

जालंधर ब्रीज समाचार पत्र को पंजाब से पत्रकारों, स्तंभ लेखकों, फोटोग्राफरों, बिजनैस प्रतिनिधियों की तुरन्त आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार दिया जाएगा
मोबाइल
99881-15514

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

PUNHIN01927-TC

आवश्यकता

जालंधर ब्रीज समाचार पत्र को पंजाब से पत्रकारों, स्तंभ लेखकों, फोटोग्राफरों, बिजनैस प्रतिनिधियों की तुरन्त आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार दिया जाएगा
मोबाइल
99881-15514

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 29 JULY TO 4 AUGUST 2019 • VOLUME-2 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर हादसों का खौफ

खुले हुए बेरीकेटस और टूटी हुई लोहे की जालियां किसी भी वक्त बन सकती है लोगों की जान का खतरा

■ जालंधर/अतुल शर्मा

भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रमार्ग जहां की हर एक राज्य से लोग निकलते है पर उनको यह नहीं पता की वह अपने घर वापिस अपने पारिवारिक सदस्य को मिल पाएंगे के नहीं। क्योंकि जिस नेशनल हाईवे से वह निकल रहे है उस सड़क के दोनों तरफ से लगाए गए बेरीकेटस और जालियां टूटी हुई है और किसी भी समय कोई जानवर या कोई इंसान उनके सामने आ सकता है और वह जिस स्पीड से आ रहे होते है उनके लिए ये काफी मुश्किल होगा की वो उस समय अपनी गाड़ी को धीरे कर पाए।

इसी बीच उनकी गाड़ी अपने से अनकट्रोल हो के कहीं न कहीं जा रही दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों से टकरा जाती है और उसमें बैठे उनके सारे पारिवारिक सदस्य को अपनी जान खोनी पड़ती है। ये हादसा किसी की भी जिन्दगी में हो सकता है। चाहें वह आमिर हो या गरीब, अफसर हो या नेता, क्योंकि जब तक हमारे नेशनल हाईवे अधिकारियों द्वारा खुले हुए बेरीकेटस और टूटी हुई जालियां की तरफ ध्यान ना दिया गया तो लोगों की जान की जिम्मेदारी उन लापरवाह अधिकारियों की होगी।

नेताओं की आपसी खीचांतानी से अवांछित तत्वों द्वारा पुनः अनाधिकृत निर्माण शुरू

■ जालंधर/विजय कुमार

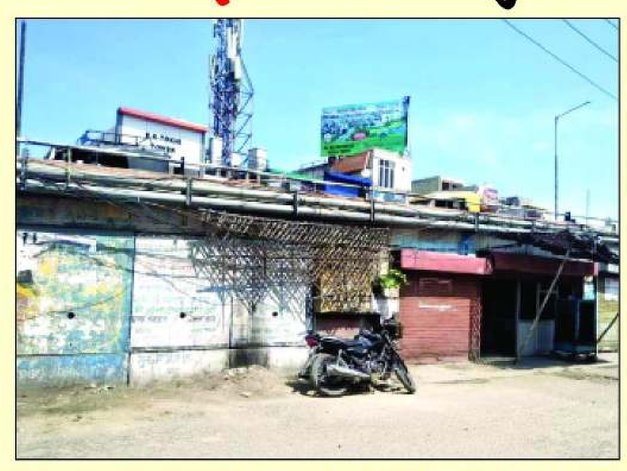

नवजोत सिंह सिद्ध के कार्यकाल में अनगिनत निर्माण रूका हुआ था, कई जगह निर्माण गिराये भी गये थे, परन्तु जब से सिद्धू और कैप्टन में सियासी रंजिश की बात सामने आई है तब से रामामंडी फ्लाई ओवर के नीचे पुनः कई दुकानदारों द्वारा गोदाम बनाना और टीन की शैड्स बगैरह बनाना शुरू हो गया है। रामामंडी चौक के पास एक स्कूटर स्टैंड बना दिया गया है और कुछ फ्रूट की रेहडियों द्वारा सारा रास्ता ही रोक दिया गया है। क्या जालंधर कार्पोरेशन के अधिकारियों व ट्रैफिक पुलिस का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है? होशियारपुर से आने वाली बसों से मोड़ पर उतरने वाली सवारी की सुरक्षा और रेहड़ियों और प्राईवेट बसों द्वारा लगाए जा रहे जाम को रोकने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की नहीं है? माननीय कमिश्नर साहब जालंधर कार्पोरेशन एवं माननीय एस.पी. ट्रैफिक पुलिस इस पर बनती हुई कारवाई करें जिससे इस अति संवेदनशील फ्लाई ओवर जिसके नीचे से सैंकड़ों यातायात चलता है जहां पुलिस स्कूल जहानखेलां के लिए पुलिस की गाड़ियां और मिलिट्री एवं वायुसेना विभाग की अनेकों गाड़ियां आदमपुर हवाई अड्डे के लिए गुजरती है। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की एवं अन्य राज्यों की बसों का यही रास्ता है। आतंकी गतिविधियों के दृष्टिगत इस अति संवेदनशील पुल (फ्लाई ओवर) की ओर विशेष निगरानी की आवश्यकता है। फ्लाई ओवर के नीचे संदिग्धों द्वारा कोई भी आपराधिक गतिविधि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन से अनुरोध है कि इस पुल (फ्लाई ओवर) की सुरक्षा की आवश्यकता है।

स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशनर कृप्या ध्यान दें

■ जालंधर/विशेष रिपोर्ट

प्राय देखने में आ रहा है कि प्राईवेट बसों में कंडकटर्स द्वारा जालंधर बस स्टैंड़ से लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी के लिए सवारी नहीं चढ़ाई जाती और अगर रामामंडी दकोहा से स्टूडैंट या अन्य कोई सवारी चढ़ाई जाती है तो उससे 15-20 रुपये लेने पर भी टिकट नहीं दिया जाता। अगर कोई सवारी टिकट मांगती है तो उससे गलत व्यवहार किया जाता है। जालंधर से लुधियाना तक की बसें भी लवली यूनिवर्सिटी की सवारी नहीं लेती जबकि देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से भी स्टूडैंट यहां पड़ने आते है क्यों पंजाब रोड़वेज के किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं जाता कि दूसरे देशों और अन्य प्रांतों में भी पंजाब की ट्रांसपोर्ट विभाग की छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। पंजाब के परिवहन मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री स्टूडैंट की इस परेशानी को मुख्य रखते हुए इस ओर ध्यान देंगे कि पंजाब रोडवेज की खाली बसें तो रोड़ पर भागती रहती है पर यूनिवर्सिटी की सवारी नहीं चढ़ाते। क्या स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर और डायेरेक्टर इस ओर ध्यान देने की कृप्या करेंगे कि प्राईवेट बसों द्वारा टिकट न देकर राजस्व को घाटा हो रहा है ओर पंजाब रोडवेज जालंधर और लुधियाना डिपों के जरनल मैंनेजर स्टूडैंट की इस बात पर ध्यान देंगे। पैसे लेकर टिकट न देना कानूनी अपराध है और उपभोक्ता के हितों का हनन है इसलिए परिवहन विभाग को हर संभव कदम उठाना चाहिए।

सत्ता संभालते ही येदियुरप्पा का बड़ा फैसला, 'टीपू जयंती' समारोह रद्द

■ बेंगलुरु/ब्यूरो

पूर्ववर्ती मैसूर साम्राज्य के 18वीं सदी के विवादित शासक टीपू सुल्तान की जयंती पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह को कनार्टक की भाजपा सरकार ने मंगलवार को रद्द कर दिया। इस समारोह का आयोजन 2015 से हो रहा था। बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने सत्ता में आने के तीन दिन के भीतर यह आदेश पारित किया। एक दिन पहले ही राज्य विधानसभा में येदियुरप्पा की सरकार ने विश्वासमत हासिल किया था। सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2015 में टीपू जयंती के अवसर पर 10 नवंबर को वार्षिक समारोह के आयोजन की शुरुआत की थी और भाजपा एवं अन्य के विरोध के बावजूद एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जदएस की गठबंधन सरकार ने पिछले साल भी इसे जारी रखा था। आदेश में कहा गया है कि विराजपेट के विधायक के. जी. बोपैया ने येदियुरप्पा को पत्र लिखकर राज्य के कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा टीपू जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले वार्षिक समारोहों को रद्द करने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने ऐसे समारोह को लेकर विशेषकर कोडागू जिले में होने वाले विरोध की ओर ध्यान आकृष्ट किया। वर्ष 2015 में इसके पहले आधिकारिक आयोजन के दौरान कोडागू जिले में व्यापक प्रदर्शनों और हिंसा में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ता कटप्पा की मौत हो गयी थी। भाजपा और दक्षिणपंथी संगठन टीपू को ''धार्मिक कट्टरपंथी'' बताते हुए जयंती समारोहों का कड़ा विरोध करते रहे हैं।

गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस सांसद संजय सिंह का राज्यसभा से इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होंगे

■ लखनऊ-अमेटी/ब्यूरो

नेहरू-गांधी परिवार के बेहद करीबी और कांग्रेस के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेठी के राजा संजय सिंह अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कांग्रेस ने असम से राज्यसभा भेजा था और अगले साल सदस्यता खत्म होने वाली थी। दिलचस्प बात ये है कि संजय सिंह ने इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार के मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि वह हार गए थे। तीसरे स्थान पर रहे थे। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह फिलहाल अमेठी से बीजेपी की विधायक हैं। बता दें कि संजय सिंह कई बार यूपी में विधायक और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। यूपी में मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। याद रहे कि संजय सिंह नेहरू-गांधी परिवार के करीबी जरूर माने जाते हैं, लेकिन अतीत में वो बीजेपी और जनता दल का दामन भी थाम चुके हैं।

एपल की मुश्किलें बढ़ीं, ट्रंप ने चीन से पार्ट्स खरीदने पर कड़ा कदम उठाने की चेतावनी

■ वॉशिंगटन/ब्यूरो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टेक जाइंट एपल की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम उठाया है। एपल के सीईओ टिम कुक को चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कंपनी मैक प्रो कम्प्यूटर के पार्ट चीन में बनाएगी तो उसे आयात शुल्क में छूट नहीं मिलेगी। डोनल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी ट्वीट कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, एप्पल को मैक प्रो के चीन में बनने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। इन्हें अमेरिका में बनाएं, फिर इन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के बावजूद एप्पल कथित तौर पर अपने नए लॉन्च हुए मैक प्रो डेस्कटॉप कम्प्यूटर का उत्पादन चीन में करने की योजनी बना रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, टेक कंपनी ने ताइवान के क्वांटा कम्प्यूटर इंक को 6,000 डॉलर के डेस्कटॉप कम्प्यूटर के निर्माण के संबंध में बात की है और शंघाई के पास एक फैक्टरी में उत्पादन की तैयारी कर रही है।

पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन तोड़ा सीजफायर, एक जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 2 पाक रेंजर्स ढेर

■ श्रीनगर/ब्यूरो

पाकिस्तानी सेना ने आज लगातार तीसरे दिन सीजफायर का उल्लंघन किया. राजौरी, तंगधार और कुपवाड़ा में पाकिस्तानी रेंजर्स ने दोपहर करीब डेढ़ बजे गोलीबारी की। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गए और दो नागरिक घायल हो गए. वहीं भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के दो जवानों को मार गिराए। सूत्रों ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के चलते तंगधार में सीमावर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सनिकों ने सोमवार को भी बगैर किसी उकसावे के गोलाबारी की थी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा था, पाकिस्तान ने संघर्षविराम का उल्लंघन कर पुंछ जिले में शाहपुर सेक्टर में एलओसी पर गोलीबारी और मोर्टार से हमले कर दिए। रविवार को भी इसी सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की थी, गोलीबारी के दौरान दो आम नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए थे।

तीन तलाक बिल का विपक्ष ने किया विरोध

कहा-यह मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला कदम

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों के साथ साथ अन्नाद्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस ने भी तीन तलाक संबंधी विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग की।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका मकसद ''मुस्लिम परिवारों को तोड़ना'' बताया। उच्च सदन में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया कि जब तलाक देने वाले पति को तीन साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा तो वह पत्नी एवं बच्चे का गुजारा भत्ता कैसे देगा?

उन्होंने कहा, ''यह घर के चिराग से घर को जलाने की कोशिश'' की तरह है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद ''मुस्लिम परिवारों को तोड़ना'' है।

उन्होंने कहा कि इस्लाम में शादी एक दिवानी समझौता है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आप इसे संज्ञेय अपराध क्यों बना रहे हैं? उन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की।

संघ के स्कूल से देश सेवा के लिए तैयार होंगे अनुशासित सैनिक

■ विशेष रिपोर्ट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया 1994 से 2000 तक सरसंघचालक के पद पर रहे। रज्जू भैया पहले गैर महाराष्ट्रियन और पहले गैर ब्राह्मण सरसंघचालक थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। छह साल तक संघ की कमान संभालने वाले रज्जू भैया के कहने पर नानाजी ने मंत्री पद ठुकरा दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 2025 में जिसकी उम्र 100 बरस हो जाएगी। लेकिन यह एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। समाज के भीतर देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर आरएसएस अपनी पहचान कराता है। इतिहास के पन्नों से गुलाम हिन्दुस्तान की यादों में हिंदुत्व की आस्था से भारतीयता की भावना में रचे-बसे इस संगठन का जन्म तो 94 साल पहले हुआ था। उस वक्त सिर्फ 12 लोग थे लेकिन आज करोड़ों-करोड़ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संगठन की हामी हैं। आरएसएस का इरादा अखंड भारत का है और संघ का वादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पन्नों में भटकता है। फरवरी 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सेना को सैन्यकर्मियों को तैयार करने में छह-सात महीने लग जाएंगे, लेकिन संघ के स्वयं सेवकों को लेकर यह तीन दिन में तैयार हो जाएगी। यह हमारी क्षमता है पर हम सैन्य संगठन नहीं, पारिवारिक संगठन हैं लेकिन संघ में सेना जैसा अनुशासन है। अगर कभी देश को जरूरत हो और संविधान इजाजत दे तो स्वयं सेवक मोर्चा संभाल लेंगे। उस वक्त इस बयान को लेकर पूरे देश में खूब राजनीति भी हुई थी। लेकिन संघ प्रमुख द्वारा कही गई बात के एक साल बाद आरएसएस देश के लिए सेना तैयार करने की भूमिका में है।

ट्विटर

आजम खान ने माफी मांग ली है। उम्मीद है कि अब कोई सदस्य इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा, जो किसी सदस्य या समुदाय को आहत करने वाली साबित हो।

- रमा देवी, भाजपा सांसद

उक्ति

अनुभव हासिल करने के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता है, मगर इससे जो शिक्षा मिलती है, उससे उत्तम शिक्षा दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं दे सकता।

-विंस्टन चर्चिल

दखल

बाढ़ और सूखे की दुविधा

जल प्रबंधन की परियोजनाएं बनना और लागू होना एक-दो माह का काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए चार-छह साल का वक्त लगता है। फिलहाल कुछ कर सकते हैं तो इतना कि बाढ़ और सूखे के बाद राहत और दूसरी तैयारियां अभी से करके रख लें। लेकिन उससे बड़ा काम यह होना चाहिए कि जल संभरण या संचयन की योजनाओं पर सोचना शुरू कर दें। खासतौर पर वैसी योजनाएं जो पानी को रोक कर सकती हों।

देश में मानसून के मुख्य चार महीने ही होते हैं। दो माह गुजरने को हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि अब तक औसत से 17 फीसद पानी कम गिरा है। यानी इस साल सूखे का अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि अभी पूरा मानसून गुजरा नहीं है। दो महीने और बचे हैं। हो सकता है कि ताबड़तोड़ बारिश हो जाए और इस साल पूरे मानसून में सामान्य बारिश का सरकारी अनुमान सही भी साबित हो जाए। लेकिन दो महीने में अगर औसत से सवा गुनी बारिश हो गई तो देश में कई जगह भयावह बाढ़ का खतरा खड़ा हो जाएगा। देश में इस समय तक जो हालात बने हैं, उनसे भयानक बाढ़ या भीषण सूखे के आसार बराबर के बन गए हैं। ऐसे हालात को प्रबंधन प्रौद्योगिकी के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए।

बीस दिन पहले तक देश के कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बन रहे थे। जून महीने में बारिश औसत से 33 फीसद कम हुई थी। पिछले महीने मीडिया में सूखे तालाबों में गड्ढे खोद कर पानी ढूंढने और टैंकरों से पानी लेने के लिए लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें छप रही थीं। उसके बाद जुलाई में पांच-सात दिन कुछ ज्यादा बारिश हो गई और देश में कई जगह बाढ़ के हालात तक बन गए। हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि जुलाई के चौथे हफ्ते तक देश में कुल बारिश औसत से सत्रह फीसद कम हुई है, इसके बावजूद कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं। यानी इस साल के मानसून की बेतरतीब चाल ने इस दुविधा में डाल दिया है कि हम बाढ़ से ज्यादा चिंतित हों या सूखे से? या इस बार बाढ़ और सूखा दोनों ही संकटों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? एक ही साल में बाढ़ और सूखे की स्थिति को मानसून की गड़बड़ी की बजाय जल प्रबंधन के नजरिए से देखने की दरकार है।

जल विज्ञानी और जल प्रबंधक कई साल से बार-बार बताते आ रहे हैं कि देश में पानी की समस्या का समाधान बारिश से मिले खरबों घनमीटर पानी को रोक कर रखने से ही संभव है। यही एकमात्र उपाय है जो बाढ़ और सूखे से निजात दिला सकता है। इसीलिए इस साल बांध और जलाशयों में पानी रोक कर रखने की मौजूदा स्थिति पर नजर डालनी जरूरी है। देश के बांधों व जलाशयों पर हफ्ते दर हफ्ते निगरानी रखने वाले केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) के मुताबिक, इस समय तक देश के सभी मुख्य बांधों में सिर्फ 257 अरब घनमीटर पानी रोक कर रखने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि देश की धरती पर बरसे कुल पानी में हर साल हमें औसतन एक हजार आठ सौ अरब घनमीटर पानी उपलब्ध होता है। बाकी पानी नदियों को उफनाता और बाढ़ की तबाही मचाता समुद्र में वापस चला जाता है। यही नहीं, अपने बांधों की 257 अरब घनमीटर क्षमता भी कहने को ही है, क्योंकि मानसून के बाद इस्तेमाल के लिए इन बांधों की पानी जमा करने की क्षमता (लाइव स्टोरेज) सिर्फ 161 अरब घनमीटर ही है। बाकी 96 अरब घनमीटर पानी वह है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह डेड स्टोरेज कहलाता है। कई कारणों से इस पानी को निकालने की मनाही होती है। डेड स्टोरेज इसलिए बनाया जाता है ताकि भूजल रिचार्ज होता रहे और उस इलाके का पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। डेड स्टोरेज पानी के साथ बह कर आने वाली मिट्टी के कारण बांध को जल्दी बेकार हो जाने से भी रोकते हैं।

जल आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 161 अरब घनमीटर संभरण क्षमता वाले बांधों में जुलाई माह के आखिरी सप्ताह तक सिर्फ 40 अरब घनमीटर पानी ही भरा जा सका है। पिछले साल इस समय तक यह आंकड़ा 65 अरब घनमीटर का था। उस हिसाब से इस साल अब तक जल भंडारण पिछले साल से 38 फीसद कम हुआ है। यहां इस बात पर गौर होना चाहिए कि पिछले साल सामान्य से छह फीसद ही कम बारिश हुई थी, मगर देश का लगभग आधा हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया था। इसका एक मतलब यह निकलता है कि इस साल के हालात पिछले साल से ज्यादा गंभीर हैं। हालांकि, यह अलग बात है कि देश का मौसम विभाग अभी भी पूरे मानसून में औसतन सामान्य वर्षा की उम्मीद में है। लेकिन यह हिसाब अभी नहीं लगा है कि अगर मानसून के बाकी बचे समय में औसत से 20 फीसद ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ से तबाही का आकार कितना बड़ा होगा। और अगर सामान्य से ज्यादा बारिश न हुई तो सूखा पड़ना लगभग तय है। बेशक, यह ऐसी आफत है जिसका फौरन ही कोई हल नहीं निकाला जा सकता। जल प्रबंधन की परियोजनाएं बनना और लागू होना कोई एक-दो महीने का काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए चार-छह साल का वक्त लगता है। फिलहाल कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कि बाढ़ और सूखे के बाद राहत व दूसरे काम की तैयारियां अभी से कर लें।

उससे बड़ा काम तो यह होना चाहिए कि देश में जल संभरण या संचयन की बड़ी योजनाओं पर सोचना शुरू कर दें। खासतौर पर वैसी जल योजनाएं जो थोक में पानी को रोक कर सकती हों। फिर कुदरती आपदाओं से कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिशें अभी से होनी चाहिए। और अगर बाढ़ और सूखे से बचाव करना है तो बारिश के पानी को नदियां उफनाते हुए, बाढ़ की तबाही मचाते हुए वापस समुद्र में जाने से रोकने के लिए नए बांध और जलाशय बनाने पर सोचना ही पड़ेगा। वैसे इस काम के लिए भी हमने अपने लिए बहुत सारे व्यवधान खड़े कर रखे हैं। इससे अलग एक मसला यह भी है कि जो बांध, झीलें, तालाब आदि देश में मौजूद हैं उनमें से कई अपनी क्षमता के मुताबिक पूरे भर नहीं पा रहे हैं। ये बांध और तालाब क्यों नहीं भर पाते हैं, कम से कम इसके कारणों को खत्म करने के काम पर फौरन ही लगा जा सकता है। मसलन जिस भी बांध, जलाशय या दूसरे जल निकाय के जल ग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में गड़बड़ियां पैदा कर दी गई हैं, उन्हें फौरन सुधारा जाए। जल ग्रहण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां बरसा पानी किसी जल निकाय में जाकर जमा होता है। लेकिन कई जगह ऐसी सड़कें या रिहायशी इमारतें बन गई हैं कि जलाशय तक पानी जाने के रास्ते ही बंद हो गए हैं।

यही कारण है कि अच्छी बारिश के बावजूद कई बांध, तालाब और कुंड भर ही नहीं पाते और इसी कारण शहरी इलाकों में जलभराव व बाढ़ की समस्या बढ़ गई है। इसी वजह से जमीन के भीतर भी पानी नहीं पहुंच पाता। जल विज्ञान के विशेषज्ञ इसके समाधान के लिए 'जलग्रहण क्षेत्र उपचार' (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) नाम का एक उपाय सुझाते हैं। हाल फिलहाल अगर और कुछ न हो सकता हो तो सरकार कम से कम ऐसे उपायों पर विचार-विमर्श तो शुरू करवा ही सकती है। इस बात पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि जल संचयन की परियोजनाएं बहुत खर्चीली हैं। बांधों-तालाबों से गाद निकालने का काम भी खर्चीला है। जलग्रहण क्षेत्र उपचार का काम भी भारी-भरकम है। साल दर साल बाढ़ और सूखे के कारण देश की आर्थिक वृद्धि दर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए जल संचयन पर ज्यादा खर्च करना भी मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है।

जल संरक्षण की बात रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने सांसदों से जल संरक्षण की पहल करने का अनुरोध किया था। चूंकि, लगातार घटते भूजल की समस्या का हमें पता है और यह समस्या अब किसी से अछूती नहीं रह गई है, सो हम सभी को इस दिशा में पहल शुरू करनी होगी।

विशेष संपादकीय

कामकाजी महिलाओं की राह जटिल

कब तक माफी से चलेगा काम

कार्रवाई से बचने सपा सांसद आजम खान ने सांसद रमा देवी पर विवादित बयान के लिए संसद में माफी मांग ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में संसद में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? और अगर होंगी तो उन्हें रोकने के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे।

कार्रवाई से बचने समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान ने सांसद रमा देवी पर विवादित बयान के लिए लोकसभा में माफी मांग ली है। आजम खान ने कहा कि मेरे भाषण और आचरण को पूरा सदन जानता है और मेरी भावना में कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं चेयर से माफी चाहता हूं। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि महिला सांसदों के समान को ठेस पहुंची है और अपमान हुआ है, इसलिए आजम खान को ठीक ढंग से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल, भाजपा समेत कई दलों ने साफ कर दिया था कि अगर आजम अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर, पुलिस ने आजम खान के खिलाफ 13 मामलों में चार्जशीट दायर की। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। साथ ही विधायक बेटे अदुल्ला आजम के खिलाफ भी पुलिस ने दायर की चार्जशीट, उन पर जया प्रदा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। बता दें कि शुक्रवार को कार्रवाई का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर छोड़ दिया गया था। सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद बिरला ने फैसला लिया है कि खान को बचाव का एक मौका दिया जाएगा। उनके सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा जाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर निलंबन तय है। यह निलंबन इस सत्र के बचे हुए दिनों के लिए हो सकता है। हालांकि, अब आजम ने माफी मांग ली है, तो मामला खत्म हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि या भविष्य में संसद में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? और अगर होंगी तो उन्हें रोकने के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे। महिला या फिर किसी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस तरह की बयानबाजी को बढ़ावा भी इसलिए मिलता रहा, योंकि मामला सिर्फ माफी से ही रफा-दफा कर दिया गया। आज तक न तो किसी तरह की गाइड लाइन बनाई गई और न ही किसी की तरह की सजा का प्रावधान किया गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जिस मामले पर दो दिन तक संसद ठप रही हो, महिलाओं का अपमान बताकर देश की महिला सांसदों ने आजम पर हमला बोला हो, वह दो लाइन की माफी से खत्म माना जा सकता है...हरगिज नहीं। फिर क्या किया जाए जिससे इस तरह की बयानबाजियों पर रोक लग सके। संसद को दूसरे मामलों की तरह ही इस मामले में भी कानून बनाना चाहिए। कानून में ऐसी सजा का प्रावधान हो, जिससे कोई भी नेता या सांसद और विधायक अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल न कर पाए।

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में नेताओं या उच्च पदों पर बैठे लोगों की बोली बिगड़ने से उपजे विवाद जब-तब सामने आते रहते हैं। ज्यादातर मौके पर यह बहस का मसला बनता है और सलाहें सामने आती हैं कि नेताओं को बोलते समय शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। मगर ऐसा हो नहीं रहा है।

हाल ही में यह खबर आई है कि जापान में 28 फीसदी महिलाओं ने बच्चों के लिए नौकरी छोड़ी और 50 हजार बच्चे दिनभर के लिए देखभाल वाले गृहों (डे-केयर) की प्रतीक्षा सूची में हैं। जापान में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए इस तरह के गृहों को सरकार ही चलाती है, इसलिए सभी को सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में कामकाजी माताओं के पास नौकरी छोड़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचता। यह स्थिति सिर्फ जापान की नहीं, लगभग सभी देशों की है। किसी भी संगठन में महिलाओं के नौकरी छोड़ने की घटना या संख्या में कमी आने को सामान्य तौर पर 'लीकिंग पाइपलाइन' कहा जाता है। इस विचार को सबसे पहले अमेरिका में कामकाजी महिलाओं की स्थिति की अर्थशास्त्री एन हुलिट ने अपनी पुस्तक 'क्रिएटिंग ए लाइफ: प्रोफेशनल वुमन एंड द वेस्ट फॉर चिल्ड्रन' में चर्चा करते हुए कहा कि 40 की उम्र के पड़ाव पर पहुंचीं पेशेवर अमेरिकी महिलाओं में से 42 फीसद संतानहीन थीं लेकिन उनमें से 14 फीसद ने ही यह फैसला लिया था। कारण स्पष्ट था कि पारिवारिक दायित्व कैरियर में रुकावट न बने। भारत में तो स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं। एक और तथ्य सामने आया है कि जो महिलाएं नियमित तौर काम कर रही हैं उनके बच्चों की संख्या भी कम है। ऐसी महिलाओं की प्रजनन दर 10 साल पहले 3.3 फीसदी थी, जो अब घट कर 2.9 फीसदी तक आ गई है। वहीं गैर कामकाजी महिलाओं की प्रजनन दर 3.1 फीसद के स्तर पर बनी हुई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कामकाजी महिलाएं दबाव में हैं। पर या यह किसी भी समाज के लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने 1919 में अपनी स्थापना के बाद से संस्थागत नौकरियों में महिलाओं की सहभागिता को अपनी प्रस्तावना में शामिल किया था। इसके सौ साल बाद अप्रैल-2019 में आईएलओ ने दुनिया भर में कामकाजी महिलाओं के बारे में जारी विस्तृत रिपोर्ट में हैरान करने वाले तथ्य सामने रखे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005-2015 के बीच 'मदरहुड एंप्लॉयमेंट पेनल्टी' यानी मां बनने की वजह से नौकरी नहीं कर पाने की संभावना में 38.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस तथ्य की पुष्टि हाल में एक शोध से हुई है। ब्रिटेन में एक शोध में पाया गया है कि कार्यस्थल पर हर पांचवीं गर्भवती और नई बनी मां से काम के दौरान भेदभाव किया जाता है। अमेरिका की लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि कामकाजी माता के साथ भेदभाव की खबरों के चलते गर्भवती महिलाएं भयभीत हैं और उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सताता है। इन स्थितियों में अमूमन यह तर्क दिया जा सकता है कि जब दुनिया के सभी देशों में मातृत्व अवकाश मिलता है तो यह डर क्यों? यह सच है कि लगभग सभी देश कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश देते हैं, मगर हकीकत यह है कि अधिकतर निजी संस्थान अपने यहां गर्भवती महिलाओं के सामने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिससे उन्हें नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा सके। पेशेवर एवं प्रबंधकीय पदों पर काम करने वाली महिलाओं से मां बनने के बाद भी उम्मीद की जाती है कि वे सुबह जल्दी दफ्तर पहुंचें और देर तक रुकें। जहां तक मातृत्व अवकाश का प्रश्न है, उसके साथ भी अनेक जटिलताएं देखने में आती हैं। साल 2017 में मातृत्व प्रसूति लाभ अधिनियम (संशोधित) लागू होने के बाद से ही कंपनियां महिलाओं को रखने में कतराने लगी हैं। वर्ष 2004-05 से 2011-12 में महिलाओं की निकासी की दर सात साल में कुल 28 लाख रही। संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के बाद एक साल में लाखों महिलाओं की नौकरी जाना हैरान करता है। जमीनी सच्चाई यह है कि संपूर्ण कार्य व्यवस्था लाभ-हानि के गणित पर टिकी है जिसके कारण महिलाओं को नौकरी पर रखने से कंपनियां बचती हैं। आज भी एक तिहाई कंपनियां ऐसी हैं जहां महिला कर्मचारी रखी तो गई हैं लेकिन उनकी संख्या दस फीसदी से भी कम हैं। एक सर्वे में एक चौथाई कंपनियों ने स्वीकार किया कि वे महिलाओं की तुलना में पुरुष कर्मचारियों को काम पर रखना ज्यादा पसंद करेंगी। 65 फीसद कंपनियों ने माना कि वे महिलाओं को नौकरी नहीं देना चाहतीं और इसके पीछे कारण यह है कि कंपनियों में कारोबार मुनाफे के लिए किया जाता है व सवैतनिक मातृत्व अवकाश, कंपनियों के लिए हानि का सौदा है। कामकाजी महिलाएं सिर्फ यही भेदभाव नहीं झेलती हैं, सामाजिक स्तर पर भी निरंतर उपेक्षा का सामान कर पड़ता है। स्त्री की प्राथमिक जिम्मेदारी परिवार और बच्चों की देखभाल है। आज भी दुनियाभर में महिलाएं अपनी दिनचर्या का दो-तिहाई समय घर और परिवार की देखभाल में व्यतीत करती हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1997 के मुकाबले 2012 में महिलाएं इन कामों में औसतन 15 मिनट कम समय व्यतीत करती हैं, जबकि इसी अवधि में घर के कामों में पुरुषों की हिस्सेदारी दिन भर में केवल आठ मिनट बढ़ी है। इसी गति से घर के कार्यों में पुरुषों और महिलाओं को बराबर भागीदारी हासिल कर पाने में दो सदियां लग जाएंगी। प्रश्न यह उठता है कि जब महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं घरेलू कार्यों में सहयोग करते? दरअसल, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि पुरुषों का घरेलू कार्यों में सहयोग उनकी तथाकथित 'पुरुषत्व' की छवि को चोट पहुंचाता है और यही कारण है कि विकसित समाज से लेकर विकासशील समाजों तक कई बार पुरुष स्वयं को घरेलू दायित्व और बच्चों की देखभाल से दूर रखते हैं। इस तथ्य की पुष्टि उन आंकड़ों से की जा सकती है जो जापान की ही नहीं, पूरे विश्व की पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उघाड़ते हैं। जापान में तीस हफ्ते का पितृत्व अवकाश पाने का कानून है, जहां 2017 में हर बीस में से सिर्फ एक पिता ने अपने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। ये आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि समाज ने स्पष्ट रेखा खींच रखी है और स्त्री का दायरा, घर-परिवार के लिए सुनिश्चित कर रखा है। अगर वह इससे अलग कुछ करना चाहती है तो शर्त यही है कि घर के कार्यों में व्यवधान नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या यह उचित है? आधी आबादी को साथ लिए बगैर,या कोई देश सही मायनों में तरक्की कर सकता है। भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सिर्फ 27 फीसदी महिलाएं श्रम शक्ति में हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे परिवार जो आर्थिक सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए महिला सदस्यों से नौकरी करने की अपेक्षा रखते हैं, वे उनके घरेलू दायित्वों को बांटना नहीं चाहते। ऐसे में उनके सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे मातृत्व दायित्व को निभाने के लिए नौकरी छोड़ दें या पेशेवर जिंदगी को बनाए रखने के लिए मां बनने से बचें। अब भी समय है कि महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच हम उस ठोस धरातल को ढूंढें जहां महिलाओं के पारिवारिक दायित्वों को घर के पुरुष साझा करें ताकि वे भी अपनी प्रतिभाओं को नवीन आयाम दे सकें।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे परिवार जो आर्थिक सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए महिला सदस्यों से नौकरी करने की अपेक्षा रखते हैं, वे उनके घरेलू दायित्वों को बांटना नहीं चाहते। ऐसे में उनके सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे अपने मातृत्व दायित्व को निभाने के लिए नौकरी छोड़ दें या फिर पेशेवर जिंदगी को बनाए रखने के लिए मां बनने से बचें।

कर्नाटक का पारा फिर गरम

कर्नाटक में चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले बीएस येदियुरप्पा के लोर टेस्ट से पहले स्पीकर आर. रमेश कुमार के फैसले से राज्य का सियासी पारा गरमा गया है। स्पीकर ने इस्तीफा दे चुके 14 और बागी विधायकों की सदस्यता रविवार को रद्द कर दी है। इसमें कांग्रेस के 11 और जनता दल (सेकुलर) के तीन विधायक शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को स्पीकर ने तीन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। यानी कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिरने का कारण बने सभी 17 विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य करार दे दिया है। कर्नाटक के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने रविवार को भले ही 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया हो, लेकिन इससे येदियुरप्पा की अगुआई वाली नई भाजपा सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अयोग्य करार दिए गए सदस्यों में 11 विधायक कांग्रेस के जबकि तीन जेडीएस के हैं। ये बागी विधायक इस पूरे विधानसभा के कार्यकाल यानी 2023 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी सीटों पर दोबारा उप चुनाव होने पर नए प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। वहीं, येदियुरप्पा सोमवार को बड़ी आसानी से विश्वासमत साबित कर लेंगे। देखा जाए तो इन बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना येदियुरप्पा के हित में ही है। दरअसल, 225 सदस्यों वाले कर्नाटक विधानसभा में फिलहाल भाजपा के 105 विधायक हैं। भाजपा के समर्थन में 1 निर्दलीय विधायक है। वहीं, कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों की संख्या 99 रह गई है। इसके अलावा, बसपा से निष्कासित एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक हैं। आज 14 और पहले तीन यानी कुल 17 सदस्यों को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार देने की वजह से हाउस की क्षमता अब 208 सदस्यों की हो गई है। ऐसे में बहुमत पाने के लिए 105 विधायकों का समर्थन चाहिए। इतने विधायक भाजपा के खुद के पास हैं। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद येदियुरप्पा बड़ी आसानी से विश्वास मत साबित कर लेंगे। वहीं, उन पर अयोग्य करार दिए गए विधायकों को मंत्री बनाने का नैतिक दबाव भी नहीं होगा और ऐसे में भाजपा के विधायकों में किसी तरह का असंतोष होने की गुंजाइश नहीं होगी। स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कहा है कि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया। ऐसे में अब अयोग्य ठहराए गए विधायकों के सामने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। हालांकि, बगावती तेवर अपनाकर कुमारस्वामी सरकार गिराने वाले विधायकों को कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। चूंकि, अब वे विधायक नहीं हैं, सो मंत्री पद मिलने से रहा। वहीं भाजपा भी इन विधायकों को मंत्री पद देकर उपकृत करना चाहती थी, जिसने अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकी हैं।

कर्नाटक के स्पीकर आर. रमेश कुमार ने इस्तीफा दे चुके 14 और बागी विधायकों की सदस्यता रविवार को रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद राज्य का सियासी पारा गर्म हो गया है। हालांकि, इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का असर भाजपा सरकार पर नहीं होगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN01927, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

बिजनेस

विदेशी मुद्रा भंडार नए रिकार्ड स्तर पर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 1.58 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 430 अरब डॉलर के पार 430.38 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में यह 1.11 अरब डॉलर घटकर 428.80 अरब डॉलर पर रहा था। इसका पिछला उच्चतम स्तर 05 जुलाई को समाप्त सप्ताह में दर्ज किया गया था जब यह 429.91 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक के जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.39 अरब डॉलर बढ़कर 401.09 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान स्वर्ण भंडार 24.30 अरब डॉलर पर स्थिर रहा।

न्यूज

सिप्ला ने दवा उद्योग के लिए अनुकूल नीति की मांग की

नई दिल्ली। घरेलू दवा कंपनी सिप्ला ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के लिये आवंटन बढ़ाने, कारोबार सुगमता को बेहतर बनाने तथा घरेलू दवा उद्योग की मदद के लिये नीतियां तैयार करने का सरकार से अनुरोध किया है। कंपनी के चेयरमैन वाईके हमीद ने 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि आबादी तथा बीमारियों के बोझ को देखते हुए देश में मूलभूत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को हमेशा विशेष ध्यान की जरूरत होगी। भारत को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को लेकर नियम बनाने होंगे जो घरेलू दवा उद्योग तथा देश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जरूरतों के अनुकूल हो। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ाना वक्त की जरूरत है। एक दवा कंपनी होने के नाते हम बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने और कारोबार को सुगम बनानेए बेहतर नियामकीय ढांचा तैयार करने, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने तथा किफायती एवं लोगों के लिये सुलभ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के साथ ही दाम पर संतुलित नियंत्रण में समर्थन की उम्मीद करते हैं।

हुवावेई का पॉपअप सेल्फी कैमरा फोन जल्द आएगा

नई दिल्ली। मोबाइल फोन बनाने वाली चीन की कंपनी हुवावेई भी पॉप अप सेल्फी कैमरा के रेस में शामिल होते हुए गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन वाई 9 प्राइम लॉंच करने जा रही है। यह फोन ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन पर सूचीबद्ध हो चुका है और इच्छुक ग्राहकों को इसके लॉंच होने पर नोटिफाइ करने के लिए पंजीयन करने का विकल्प दिया गया है। कंपनी ने इस वर्ष मई में इस फोन को चीन में लॉंच किया था जिसका स्क्रीन 6.59 इंच का है। इसमें हुवावेई किरिन 710 सिस्टम ऑन चिप है। इसमें चार जीबी रैम और 128 जीबी रोम है जिसे 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 16 एमपी, आठ एमपी और दो एमपी का ट्रिपल रियर कैमरा और 16 एमपी का पॉप अप सेल्फी कैमरा है। सभी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित है। इसमें 4000 एमएएच की बैटरी है और यह एंड्रायड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है।

सीएससी 6000 अकादमी केंद्र स्थापित करेगी

नई दिल्ली। साझा सुविधा केंद्रों का प्रबंध करने वाली कंपनी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया अगले तीन महीने में देशभर में 6000 सीएससी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। कंपनी ऐसे 3.5 लाख से अधिक सीएससी का प्रबंधन करती है। ये शिक्षण केंद्र या अकादमी केंद्र सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के पाठ्यक्रमों की पेशकश करेंगे। सीएससी ई गवर्नेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने कहा, शिक्षा सीएससी का आधार है। हम तीन महीने में ब्लॉक स्तर पर 6000 सीएससी अकादमी केंद्र स्थापित करेंगे। इन केंद्रों के जरिये हमारे भागीदारों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।

जेएलएल इंडिया का राजस्व 17 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। संपत्ति संबंधी परामर्श देने वाली कंपनी जेएलएल इंडिया का राजस्व 2018-19 में रीयल एस्टेट की मंदी के बाद भी 17 प्रतिशत बढ़कर चार हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी की वृद्धि की रफ्तार को जारी रखने के लिये इस साल अंत तक दो हजार कर्मचारी नियुक्त करने की योजना है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नायर ने कहा कि वाणिज्यिक रीयल एस्टेट विशेषकर ऑफिस स्पेस की मांग आने से राजस्व में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अभी कंपनी में करीब 11500 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक दो हजार नये लोगों को नियुक्त करने की योजना है।

कॉरपोरेट कर्ज पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जल्द

नई दिल्ली। कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने कॉरपोरेट ऋण में द्वितीयक बाजार विकसित करने के लिए जरूरी नीति और नियामकीय सुझाव देने के लिए कार्यबल का गठन किया था। भारत में द्वितीय कर्ज बाजार अभी काफी कुछ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को की जाने वाली बिक्री और बैंकों सहित कुछ अन्य वित्तीय कंपनियों को तदर्थ बिक्री करने तक सीमित है। बाजार को मजबूत करने के लिए कोई औपचारिक तंत्र विकसित नहीं किया गया है। पूंजी बाजार को मजबूत करने के प्रयासों के हिस्सों के रूप में ए केंद्रीय बैंक अगस्त अंत तक एक और रिपोर्ट पेश कर सकता है। यह रिपोर्ट आवास वित्त प्रतिभूतिकरण के विकास पर होगी। सूत्रों ने कहा कि अगले महीने के अंत दोनों रिपोर्ट आने की उम्मीद है। आरबीआई ने मई में दो समितियां गठित की थी। इनमें से एक आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास और दूसरी कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने से जुड़ी है।

अक्टूबर में तीसरी इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में

40 हजार गांवों को एक साल में कनेक्ट करें ऑपरेटर

नई दिल्ली। दूरसंचार , इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के 40 हजार गांव अभी भी दूरसंचार सेवाओं की पहूंच से दूर हैं और टेलीकॉम ऑपरेटरों को एक वर्ष में इन गांवों को कनेक्ट करना चाहिए। एशिया के सबसे बड़े टेक शो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस वर्ष 14 से 16 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली में आयोजन किया जायेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। श्री प्रसाद ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तीसरे संस्करण की घोषणा करते हुये कहा कि मोबाइल क्रांति के इस युग में भी देश में 40 हजार गांव इन सेवाओं की पहुंच से दूर हैं। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटरों के प्रमुखों के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठा गया है और इस पर उनसे काम शुरू करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों को एक वर्ष या उससे कम समय में ही इन गांवों को कनेक्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन , 70 करोड़ स्मार्टफोन और 70 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है।

40 देशों की 300 से अधिक कंपनियां लेंगी भाग

दुनिया भर के 40 से अधिक देश, 300 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां और पांच हजार से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक सालाना कार्यक्रम है जिसमें भारत की शीर्ष पायदान की दूरसंचार एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनियां हिस्सा लेती हैं। उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों, ब्रांड्स इनोवेटर, अमादमिक प्रतिनिधियों एवं नीति निर्माताओं से आग्रह करते हुये कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हिस्सा लेकर इसे एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी शो बनाने में योगदान दें। उन्होंने उम्मीद जतायी कि सभी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों के साथ डिजिटल इंडिया का उत्सव मनाने वाला यह कार्यक्रम जबरदस्त सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर के डिजिटल अर्थव्यवस्था में मोबाइल क्षेत्र का योगदान 20 से 25 प्रतिशत का होगा।

छह लाख लोगों को मिला है रोजगार

भारत को दुनिया के लिए मोबाइल उपकरण का सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र बनाने का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि देश में अभी 268 मोबाइल विनिर्माण संयंत्र है जिसमें छह लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस मौके पर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बार मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे। दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई तथा दूरसंचार विभाग इसका आयोजन करता है।

शेयर समीक्षाः कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी बाजार की नजर

निवेशकों से सतर्कता बरतने की सलाह

मुंबई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि शेयर बाजार में गिरावट का जो रुख बना हुआ है उसके मद्देनजर निवेशकों को गिरावट में निवेश के लिए तेजी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि अभी सतर्कता बरतते हुए बाजार की चाल को पहचाने और फिर निवेश करने का समय है। निवेशकों को सतर्कता के साथ बाजार की चाल पर नजर रखने की अपील करते हुये कहा कि वर्तमान माहौल में खुदरा निवेशकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि विदेशी निवेशक अभी भी निकासी में लगे हुये हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर कई कारकों के साथ ही वैश्विक स्तर के कमजोर रुख के कारण बिकवाली हावी है। उन्होंने कहा कि बाजार अभी जिस स्तर पर है उसमें लिवाली की अधिक संभावना है लेकिन इस समय अधिकांशतः मुनाफावसूली के उद्देश्य से निवेश किया जाता है जो अधिक समय तक टिकता नहीं है और इसके कारण फिर से बिकवाली होने लगती है। इसके मद्देनजर खुदरा निवेशकों को बाजार में सर्तक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह कंपनियों के तिमाही परिणामों के साथ ही कई महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं और बाजार की चाल पर इसका भी असर होगा। कारों की बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। बिकवाली का रुख बीते सप्ताह भी बना रहा जिससे शेयर बाजार बजट पेश किये जाने के बाद से लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट लेकर बंद हुआ है। बीएसई का सेंसेक्स 454.22 अंक अर्थात करीब 1.20 प्रतिशत गिरकर 38 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 37882.79 अंक पर आ गया। इस दौरान निफ्टी 1.18 प्रतिशत अर्थात 134.95 अंक उतरकर 11284.30 अंक पर रहा।

इन कंपनियों के परिणाम इस सप्ताह

इस सप्ताह एचडीएफसी, आईटीसी, भारती एयरटेल, डीएलएफ, रेड्डीज लैबरोट्रीज, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के तिमाही परिणाम आएंगे। विशेषज्ञों के इसके अलावा बुनियादी ढांचा उत्पादन और पीएमआई के आंकड़ों का असर भी निवेशकों पर पड़ने की संभावना है। वैश्विक मोर्चे की बात करें तो सबकी निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर से जुड़े फैसले पर है। कंपनियों की कमाई के निराशाजनक आंकड़ों से भी शेयर बाजारों में गिरावट का रुख है।

टॉप 10 कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप 84433 करोड़ रुपए घटा

बीएसई सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से चार का मार्केट कैप पिछले हफ्ते 84432 करोड़ रुपए घट गया। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं छह कंपनियों का मार्केट कैप 22058.30 करोड़ रुपये बढ़ा, जो चार कंपनियों को हुए नुकसान होने के मुकाबले कम है। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक 26900.6 करोड़ रुपए घटकर 622401.90 करोड़ रुपए पर आ गया। एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 23360.6 करोड़ रुपए गिरकर 374131.53 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 22123.4 करोड़ रुपए गिरकर 769627.33 करोड़ रुपए और एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 12048.2 करोड़ रुपए कम होकर 305667.95 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं दूसरी ओर टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 11951.35 करोड़ रुपए बढ़कर 791302.89 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक का 3484.66 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 268125.39 करोड़ रुपए पर हो गया। आईटीसी का 2487.11 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 331749.04 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार पूंजीकरण 2138.61 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी के साथ 288522.40 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमकैप 1266.41 करोड़ रुपए बढ़कर 374651.29 करोड़ रुपए और इंफोसिस का 730.16 करोड़ रुपए के उछाल के साथ 338148.69 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी रही।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक रहे जुलाई में 3758 करोड़ रुपए के शुद्ध बिकवाल

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जुलाई में भारतीय पूंजी बाजार से 3758 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। इससे पिछले पांच माह तक एफपीआई निवेश में लगातार वृद्धि हो रही थी। बजट में धनाढ्यों पर कर बढ़ाने के प्रावधानों के बाद से एफपीआई बिकवाली बढ़ाए हुए हैं। प्रतिभूति डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने एक से 26 जुलाई के बीच 14382.59 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। हालांकि इसी दौरान वे बांड बाजार में 10624.15 करोड़ रुपए के शुद्ध लिवाल रहे। इस तरह इस अवधि में उनकी ओर से कुल मिला कर 3758.44 करोड़ रुपए की पूंजी की शुद्ध निकासी की गई। इससे पहले जून में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार शेयर एवं बांड में 10384.54 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मई में उन्होंने 9031.15 करोड़ रुपए, अप्रैल में 16093 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था।

एक अगस्त से फ्री हो जाएगी एसबीआई की यह सर्विस

आपकी जेब पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अगस्त से अपनी ऑनलाइन पैसों के लेन-देन से जुड़ी सर्विसेस को मुफ्त करने जा रहा है। वहीं जीएसटी काउंसिल की ओर से घटाए गए टैक्स भी एक अगस्त से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना सस्ता होने जा रहा। एक अगस्त से प्रॉपर्टी के सर्किल रेट कम हो जाएंगे। रसोई गैस की कीमतें तय होंगी। ऐसे में इन फैसलों का आपकी जेब पर सीधा असर होगा।

एसबीआई ने आईएमपीएस चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है, जो एक अगस्त, 2019 से लागू होगा। अब एसबीआई की योनो ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने वाले यूजर्स से अब किसी तरह का आईएमपीएस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इससे पहले एसबीआई ने एक जुलाई से आरटीजीएस और एनईएफटी चार्ज खत्म कर दिया था। अब आईएमपीएस चार्ज खत्म होने के बाद एसबीआई के खाताधारकों को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए कोई फीस नहीं चुकानी होगी। बैंक द्वारा जारी बयान के मुताबिक बैंक ने अपने ब्रांच नेटवर्क के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने वाले कस्टमर्स के लिए सभी स्लैब्स में एनईएफटी और आरटीजीएस चार्ज 20 फीसदी तक घटा दिए हैं। इसके साथ ही ब्रांच बैंकिंग के माध्यम से एक हजार रुपए तक के फंड ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस चार्ज भी खत्म कर दिया जाएगा।

आईएमपीएस में 24 घंटे होता है फंड ट्रांसफर

आईएमपीएस एक इंस्टंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। इसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में तुरंत ही फंड पहुंच जाता है। 24 घंटे में कभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना सस्ता होने जा रहा एक अगस्त से प्रॉपर्टी के सर्किल रेट कम हो जाएंगे। इसकी वजह से एक अगस्त से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर की रजिस्ट्री कराना 6 फीसदी सस्ता हो जाएगा। वहीं, ग्रुप हाउसिंग में 6 फीसदी और कमर्शियल में 25 फीसदी सरचार्ज खत्म करने का फैसला लिया है।

टाटा वाशिंग सोडा संयंत्र की विस्तार योजना को मंजूरी

नई दिल्ली। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोडा राख निर्माता टाटा केमिकल्स को गुजरात में उसमू वाशिंग सोडा संयंत्र के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई। इसकी अनुमानित लागत 1042.07 करोड़ रु है। आधिकारिक दस्तावेजों में यह जानकारी दी गई है।

कंपनी देवभूमि द्वारका जिले के संयंत्र की क्षमता सालाना 10.91 लाख टन से बढ़ाकर 1.13 करोड़ टन सालाना करना चाहती है। केंद्र सरकार की एक हरित समिति ने विस्तार के प्रस्ताव की जांच और निरीक्षण कर रपट दी थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। टाटा केमिकल्स को जारी ईसी प्रमाण पत्र के मुताबिक प्रस्तावित परियोजना को वन्यजीवों के लिहाज से जरूरी पूर्व अनुमति और कुछ अन्य शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई है। इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से मंजूरी भी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार 231 एकड़ के मौजूदा संयंत्र में यह विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 1042.07 करोड़ रुपए बैठने का अनुमान है। इसे पूरा होने में दो साल लगेंगे।

यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश करेंगे उद्योग के दिग्गज

टॉरेंट समूह करेगा 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश

लखनऊ। उद्योग जगत की हस्तियों ने उप्रको निवेश का पसंदीदा स्थल बताते हुए आने वाले समय में बड़ी परियोजनाओं के साथ राज्य में हजारों करोड़ रु के निवेश का ऐलान किया। उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां रविवार को यहां दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रही थीं।

सैमसंग इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच सी हान्ग ने घोषणा की कि नोएडा स्थित सैमसंग के कारखाने को श्रिनर्यात केंद्रश् में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यबल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इसलिए उत्पादन की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन प्रदेश है । टॉरेंट समूह के चेयरमैन सुधीर मेहता ने ऐलान किया कि उनका समूह उत्तर प्रदेश में 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा । इसमें पाइप्ड नैचुरल गैस पीएनजी नेटवर्क के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष अहमद अल शेख ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक है और पेप्सिको इस अवसर का उपयोग करना चाहेगी। हम भविष्य में भंडारण क्षमता स्थापित करने और शीत श्रृंखला बनाने के लिए भी निवेश करना चाहते हैं ।

यूपी बन सकता है 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था

फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने रविवार को कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत जमीन पर उतर रही परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार साबित होंगी। कृष्णमूर्ति ने कहा कि यह सेरेमनी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक और नवोन्मेष का हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। वह औद्योगिक निवेश के दूसरे चरण यानी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 65 हजार करोड़ रुपए की 250 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर आयोजित समारोह से इतर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हजारों शिल्पकार, छोटे कारोबारी और महिला उद्यमी फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी को फायदेमंद मान रहे हैं।

विस्तार के लिए पूंजी जुटाएगी हीरो इलेक्ट्रिक

नई दिल्ली। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक लाख यूनिट्स की मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर पांच लाख सालाना करने के लिए अगले तीन साल में 700 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है। हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने कहा, हम हर पहलू पर विस्तार कर रहे हैं। पीछे देखने जैसा कुछ नहीं है। डीलर नेटवर्क, लेबर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम विस्तार कर रहे हैं। हम निवेश करेंगे और इसके लिए पूंजी जुटाएंगे। उनसे पूछा गया कि कंपनी कितनी धनराशि जुटाना चाहती है तो उन्होंने कहा कि इस बार में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और कंपनी फिलहाल इस पर काम कर रही है। कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम कई चीजों के लिए कम से कम 500-700 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसमें से बड़ी राशि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट के डेवलपमेंटए रिसर्च और मार्केटिंग पर खर्च होगी।

क्यूरा के एलोवेरा जेल पेश

नई दिल्ली। क्यूरा ने अपने नए 9-इन-1 मल्टीपर्पस एलोवेरा जेल को बाजार में पेश किया है जिसे त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारने और उसे पुनर्निर्मित करने के लिए तैयार किया गया है। बालों और त्वचा पर आवश्यक लाभ पाने के लिए इस उत्पाद में एलोवेरा की प्राकृतिक गुणों को बहाल किया गया है। यह बालों और त्वचा की खोई हुई नमी को पुनर्स्थापित करता है। क्यूरा 9-इन-1 एलोवेरा जेल 99 फीसदी प्राकृतिक एलोवेराजेल है, इसकी प्राकृतिक रूप से चिकित्सा और कायाकल्प लाभों को बनाए रखने के लिए हाइजीनिक रूप से सावधानीपूर्वक पैक किया गया है। यह एक मल्टी पर्पज सौंदर्य उत्पाद है जो स्वस्थ त्वचा, बालों और स्कैल्प की देखभाल के लिए बनाया गया है। क्यूरा 9-इन-1 एलोवेरा जेल 120 एमएल में मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है।

ओशिया का टीट्री प्योर एसेंशियल आयल पेश

नई दिल्ली। ओशिया ऑर्गेनिक ने अपने टीट्री प्योर एसेंशियल ऑइल को बाजार में पेश किया है, जो कई त्वचा और बालों की समस्याओं का समर्थन करने के लिए टीट्री के लाभों के साथ मिश्रित है। यह एक शुद्ध एसेंशियल आयल है जिसे शुद्ध और प्राकृतिक अवयवों के साथ बनाया गया है। यह प्योर एसेंशियल आयल त्वचा के मुद्दों से निपटनेवाले सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है। टीट्री ऑयल का उपयोग अरोमाथेरेपी में किया जाता है जो मेलले का ऑल्टिफोलिया की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह शुद्ध टीट्री आयल प्रभावी रूप से मुंहासों के उपचार में मदद करता है, संक्रमण से बचाता है, बालों के झड़ने को नियंत्रित करता है और यहां तक कि डैंड्रफको भी दूर करता है। यह 495 रुपए में देशभर में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए हमारे पास सुनियोजित योजना

ईवी को अपनाने से शहर स्वच्छ होंगे, आयात कम होगा और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा

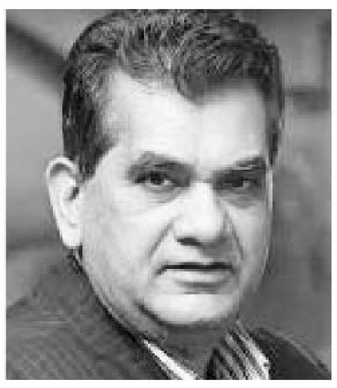

अहमदाबाद। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और बैट्री समेत इसके कलपुर्जो के लिए एक सुनियोजित योजना लागू कर रखी है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों के अपनाने से शहर स्वच्छ होंगे तथा आयात कम होगा और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने शनिवार को ऐसे वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और चार्जर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक वाहन, खासकर दोपहिया और तिपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों और बैट्री का भारत में निर्माण प्रोत्साहित करने की सुनियोजित योजना है। हमार लक्ष्य है कि हमें पहले प्रयास करना चाहिए कि दोपहिया, तिपहिया वाहनों और बसों के 80 प्रतिशत कल पुर्जे भारत में ही बने और बैट्री के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। कांत ने कहा अभी देश में बिजली से चलने वाले दोपहिया, तिपहिया और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैट्री निर्माण के भारी अवसर : अमिताभ कांत ने कहा कि देश के बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्री के विनिर्माण के लिए भारी अवसर हैं। उन्होंने कहा, पर्यावरण अनुकूल वाहनों इलेक्ट्रिक वाहनों को जितनी तेजी से अपना लिया जाए, प्रदूषण और भीड़भाड़ कम करने तथा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और रोजगार सृजन में उतनी ही अधिक मदद मिलेगी। कांत ने यहां यातायात की स्वस्थ सुविधाओं के विषय पर यहां अयोजित एक संगोष्ठी को विडियो लिंक के जरिए संबोधित किया।

प्रदूषण घटेगा और ईंधन आयात कम होगा : उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन का चालन बढ़ने से प्रदूषण कम होने के साथ-साथ पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता भी कम होगी और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में अभी प्रति 1000 आबादी पर 20 वाहन है। ऐसे में भारत के लिए पेट्रोलियम ईंधन पर आधारित परंपरागत वाहनों को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेज छलांग लगाने के भारी अवसर हैं। कांत ने कहा कि सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी और सिलिकान आधारित बैटरी की नई तकनीकों पर काम चल रहा है। भारत को बैट्री के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में तेजी से जुड़ने और बैट्री विनिर्माण बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत है।

वाहन की ज्यादातर लागत बैट्री पर : गुजरात के मुख्य सचिव जेएन सिंह ने कहा कि उनका राज्य इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में देश को दिशा दिखाने को तैयार है। इसके लिए धोलेरा एक महत्वपूर्ण कस्बे के रूप में उभर रहा है।

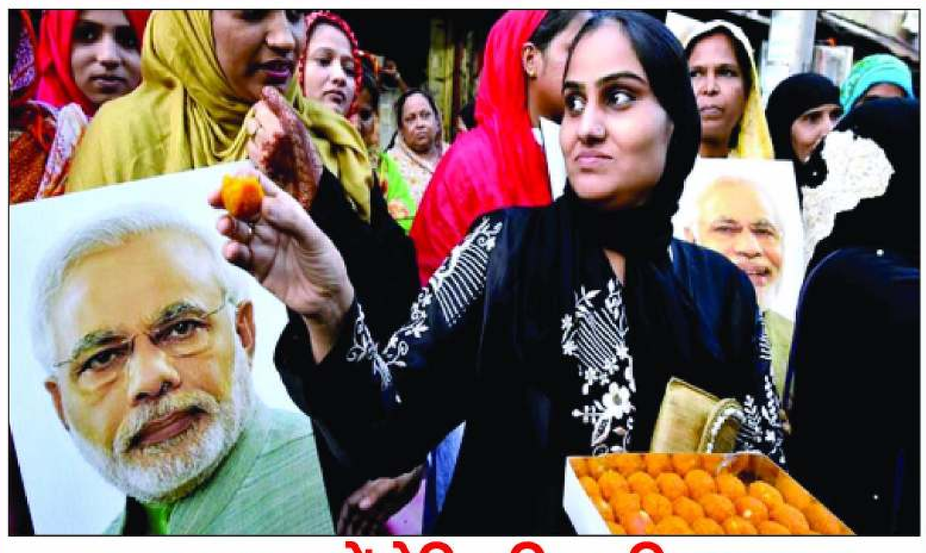

राज्यसभा में ऐतिहासिक बिल पास

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मिली आजादी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए लाये गये मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गयी और इस तरह नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा हुआ। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 मत मिले जबकि विरोध में 84 मत पड़े। मुस्लिम महिलाएं इसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थीं और मोदी सरकार ने उनका साथ देते हुए तीन तलाक विधेयक को पारित कराने के लिए पूर्व के कार्यकाल में भी प्रयास किये थे लेकिन प्रयास राज्यसभा में अटक जाते थे इस कारण बार-बार अध्यादेश से काम चलाना पड़ रहा था। राज्यसभा में तीन तलाक बिल को पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था लेकिन सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की दाद देनी होगी कि वह इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने में सफल रही। लोकसभा इसे गत सप्ताह ही पारित कर चुकी है और अब राज्यसभा की भी मंजूरी मिल जाने के बाद इसके कानून बनने की राह साफ हो गयी है। इससे पहले सुबह विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक संबंधी विधेयक मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के मकसद से लाया गया है और उसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक फैसले में इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद तीन तलाक की प्रथा जारी है।

अगस्ता वेस्टलैंड केस

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत एक दिन के लिए बढ़ी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण बुधवार तक जारी रहेगा क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अधूरी रही। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार बुधवार को सुनवाई फिर से शुरू करेंगे।

हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने 27 जुलाई को अदालत का रुख किया था और मामले में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। अदालत ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तारी से सोमवार तक अंतरिम संरक्षण दिया था जिसे बढ़ाकर मंगलवार तक कर दिया गया था।

अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 3,600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित मामले में पुरी हाल में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए थे।

गूगल के साथ मिलकर मुफ्त वाई-फाई सर्विस देगी अमेरिकी कंपनी सिस्को, बेंगलुरु से होगी शुरुआत

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

यूएस नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी सिस्को ने सोमवार को कहा कि देशभर के सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त और हाई स्पीड वाली वाई-फाई की सुविधा देने के लिए वो गूगल के साथ मिलकर जीस्टेशन का निर्माण करेगी।

सिस्कों ने बताया कि गूगल और उसके बीच की इस सहभागिता की शुरुआत सबसे पहले बेंगलुरू में होगी. उन्होंने कहा कि अभी बेंगलुरू में 25 जगहों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा दी जा रही है।

सिस्को ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में 200 और जगहों पर ये सुविधा दी जाएगी। इन स्थानों में सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टॉप, अस्पताल और सरकारी कार्यालय शामिल हैं। आने वाले वक्त में इस सेवा का विस्तार बेंगलुरू के 300 शहरों और देश के दूसरे शहरों में किया जाएगा. सिस्को इंडिया समिट 2019 में सिस्को के अध्यक्ष (भारत और सार्क) समीर गार्डे ने कहा, यह एक वैश्विक साझेदारी है और भारत पहला देश है, जहां हम इसे पूरा कर रहे हैं। बेंगलुरु में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डी-वॉयस के साथ ये सर्विस शुरू की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के बाहरी इलाके और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी इसे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इस साल फरवरी में, गूगल और सिस्को ने अपने वैश्विक गठबंधन की घोषणा की थी।

ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए नए बाजार के अवसरों को बनाने के लिए अनुमानित 8 मिलियन अतिरिक्त हॉटस्पॉट स्थापित किए जाने की जरूरत है। फिलहाल भारत में सिर्फ 52,000 वाईफाई हॉटस्पॉट हैं. सिस्को वीएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 59 प्रतिशत इंटरनेट ट्रैफिक 2022 तक सेल्युलर नेटवर्क से वाई-फाई पर लोड होने की उम्मीद है, जिसमें वाईफाई के सर्वव्यापी फैलाव का जबरदस्त मौका है।

क्या मरीजों से शुगर का इलाज छिपाया गया है ?

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

जब टाइप टू डायबिटीज सर्जरी से पूरी तरह ठीक हो सकती है तो एंडोक्रिनोलोजिस्ट उसकी जानकारी मरीजों को क्यों नहीं दे रहे। फोर्टीज मोहाली के मेटोबोलिक सर्जन डा. अमित गर्ग ने बताया शुगर का क्रांतिकारी इलाज एक सर्जरी जो टाइप टू शुगर को खत्म कर देती है लेकिन बहुत कम डाक्टर और अस्पताल इसे कर पा रहे है। भारत में मोटापा बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। मेटाबोलिक सर्जरी में पेट की थैली को अलग करवाने की नली को साथ छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है। इससे मरीज की डाईट कम और मोटापा दूर हो जाता है।

क्या कारण है कि शुगर के मरीज गोलियां खाने ओर बेहद दर्दनाक जिंदगी जीने को मजबूर है जबकि एक सर्जरी से उन्हें अच्छी जिंदगी मिल सकती है। हैरान करने वाली बात है कि आज टाइप टू डायबिटीज को मेटाबोलिक सर्जरी से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है लेकिन फिर भी मरीज को जागरूक नहीं किया जा रहा। क्या सर्जरी की जानकारी जानबूझकर छिपाई जा रही है या सच में डाक्टरों को इसकी जानकारी नहीं है। फोर्टीज अस्पताल मोहाली के बैरियाट्रिक, मेटाबोलिक और जीआई सर्जन डा. अमित गर्ग ने जालंधर के कंट्री-इन होटल में जब मेटाबोलिक सर्जरी के बारे में बताया तो पत्रकारों के मन में कई सवाल खड़े हुए। पहला सवाल यही था कि शूगर सर्जरी से ठीक हो सकती है इसकी जागरूकता इतनी कम क्यों है। डा गर्ग ने बताया कि अगर पैंक्रियाज 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता से काम कर रहे है तो यह सर्जरी सारी गोलियां छुड़वा सकती है। टाइप टू डायबटीज ठीक हो सकती है। सर्जरी से पहले हम समझने की कोशिश करते है कि मोटापे से डायबिटीज (शुगर) कैसे और क्यों होती है और उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते है।

तोंद निकलती है तो सबसे ज्यादा दबाव पैंक्रियाज पर ही पड़ता है, इसलिए मोटापा शुगर करता है।

जब शरीर के पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तब शरीर टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। यह आमतौर पर बच्चों में होती है। इंसुलिन शरीर में मौजूद शुगर को एनर्जी में तब्दील करता है। जब शुगर एनर्जी में तब्दील नहीं होती तो वह शरीर को हर अंग में जमा होना शुरू हो जाता है और शरीर के अंग खराब होना शुरू हो जाते है। पैंक्रियाज के बीटा सैल खत्म होने से जलते शरीर को रोजाना इंसुलिन की डोज बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन के सहारे जिंदगी कटती है। टाइप वन डायबिटीज को सर्जनी से ठीक नहीं किया जा सकता।

टाईप 2 डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है

दूसरी तरह की शुगर है टाइप 2 डायबीज। इसमें पैंक्रियाज से सही मात्रा में इंसुलिन नहीं निकल रहा होता है। कई बार किसी बिमारी कारण भी पैंक्रियाज खराब होने शुरू हो जाते है तब भी इंसुलिन की सही मात्रा या उनकी सेंसटिविटी कम हो जाती है। मगर टाइप 2 का सबसे बड़ा सेंस्टिविटी कम हो जाती है। मगर टाइप 2 का सबसे बड़ा कारण मोटापा है। ऐसे मरीजों में यह डायबिटीज 40 साल की उम्र के आसपास पकड़ में आती है। डाक्टर उन्हें पहले गोली देते है ओर फिर जब पैंक्रियाज और कमजोर हो जाता है व उनसे निकलने वाले इंसुलिन की मात्रा और भी ज्यादा कम हो जाती है तो बाहर से इंसुलिन के टीके लगाने पड़ते है। उम्र भर यह डोज पढती रहती है। इस डायबिटीज को टाइप टू कहते है।

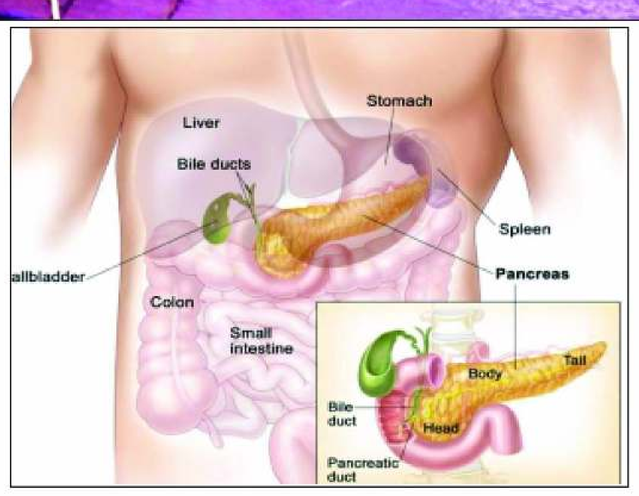

डा. अमित गर्ग ने जालंधर के कंट्री-इन होटल में जब मेटाबोलिक सर्जरी के बारे में बताया तो पत्रकारों के मन में कई सवाल खड़े हुए। पहला सवाल यही था कि शूगर सर्जरी से ठीक हो सकती है इसकी जागरूकता इतनी कम क्यों है।

इलाज- टाइप वन डाइबिटीज का कोई पक्का इलाज नहीं

टाइप 1 डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती उसके लिए मरीज को इंसुलिन बाहर से लेने पड़ते है ओर सारी उम्र उनके सहारे जाना पड़ता है। फिलहाल कोई सर्जरी नहीं है जिससे इसे ठीक किया जा सके।

टाइप 2 डायबिटीज ठीक की जा सकती है

ज्यादातर मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज मोटापे के कारण होती है। मोटापा गलत रहन सहन और खान पान के कारण होता है। कुछ मामलों में इसे रोजाना सैर, खान पान में बदलाव, खेलकूद और व्यायाम से ठीक किया जा सकता है। मगर बहुत सारे मामलों में लोग खानपान और सैर व एक्साईज से इसे ठीक नहीं कर पाते। ऐसे मरीजों के लिए मेटाबोलिक या बैरियाट्रिक सर्जरी एक उम्मीद आई है।

मोटापा डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण

फिलहाल दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है 73 प्रतिशत शहरी भारतीय मोटापे से ग्रस्त है हर किसी को लगभग 11 किलो भार कम करना है। मोटापे में पंजाबियों की बादशाहत देश में पंजाब मोटापे में नंबर वन है। खराब खान पान, रहन सहन मोटापे का बड़ा कारण। आमदनी अठठ्नी खर्चा रुपया लंबे समय तक जब शरीर ज्यादा खाता है और कम कसरत करता है तो मोटापा होता है।

सैर, खान पान में बदलाव, खेलकूद और व्यायाम से ठीक किया जा सकता है। मगर बहुत सारे मामलों में लोग खानपान और सैर व एक्साईज से इसे ठीक नहीं कर पाते। एसे मरीजों के लिए मेटाबोलिक या बैरियाट्रिक सर्जरी एक उम्मीद आई है।

याद रहे- बाएम आई 25 से नीचे ही रखें

अगर आपकी हाईट 5 फीट है तो आपका वजन 58किग्रा से अधिक नहीं होना चाहीए। अगर आप 5.8फीट लंबें है तो भार 78 किग्रा से नीचे ही रखे। दर्जनों जानलेवा बीमारियों की वजह है मोटापा, मोटापा आपके लीवर को फैटी कर देगा। जैसा शराबियों का होता है, मोटापा आपके घुटने खराब कर देगा, गठिया हो सकता है, मोटापा 13 तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। टाइप 1 की चाबी तो नहीं है लेकिन टाइप 2 डायबिटीज को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, मोटापा दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज पैदा करता है। तीन तरीकों से मोटापा ठीक किया जा सकता है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे पेट की थैली भी बड़ी हो जाती है पेट की थैली का इलाज 80 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है। सर्जरी से भार कम हुआ तो समझो कई रोगों से बच गए। सिर से पैर तक के रोगों से बचा जा सकता है। पेट की थैली को या तो अलग कर देते है या उसे छोटा कर देते है।

मिन्नी कहानी-संतुलन

शाम के समय घर जाते हुए दूर से लोगों का इकटठ दिखाई दिया। जब करीब जाकर देखा तो एक बारह-तेरह साल की लड़की रस्सी पर चलकर करतब दिखा रही थी। कभी वह सिर पर गड़वी रखके साईकिल के चक्के पर चल रही थी जिसे सब हैरानी से देख रहे थे और उसके हाथ में एक बांस था जिसके सहारे वह अपना संतुलन बनाए चल रही थी। ऐसे खेल हमने कई बार बचपन में देखे थे। आज फिर देखकर मुझे बहुत अचंभा सा लगा। उसके इस करतब को देखकर सभी लोग पैसे देने लगे और लड़की अपने ध्यान को केन्द्रित करके रस्सी पर चलती रही। उस लड़की का बाप लोगों द्वारा दिए गए पैसे इकट्ठे कर रहा था। यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई कि यह लड़की बचपन से ही अपने मां-बाप का और घर का गुज़ारा चलाने के लिए मेहनत कर रही है और आगे चलकर इसे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उस लड़की को चलते देखकर एकदम ऐसा लगा कि जैसे व्यक्ति अपने घर परिवार की ज़रुरतों को पूरा करने के लिए संतुलन बनाए अपने कई सपनों को मारकर अपने घरवालों की सभी तमन्ना को पूरा करने के लिए इस लड़की की तरह ज़िंदगी की रस्सी पर लगातार चलता रहता है। इस सोच-विचार में मैं अपने घर पहुंच गया।

- विनोद फकीरा
स्टेट अवार्डी, आर्य नगर,करतारपुर,जालंधर
मोबाइल 98721-97326
vinodfaqira8@gmail.com

रॉकेट मैन

चंद्रयान-2 लॉन्च कर बन गए देश के हीरो

बिना चप्पल के गुजरा था इसरो अध्यक्ष के सिवन का बचपन

नई दिल्ली/ब्यूरो

हाल ही में भारत ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया है। इस मिशन को लॉन्च करने में इसरो की पूरी टीम जुटी हुई थी और पूरी टीम को दिशा-निर्देश दे रहे थे इसरो चीफ कैलाशवडीवू सिवन यानी के. सिवन. तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक गांव से निकलकर इसरो प्रमुख के पोस्ट तक पहुंचने में सिवन को न जाने कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ी। लेकिन, एक बात साफ है कि इन दूरियों को तय करने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

किसान के घर जन्में सिवन की स्कूली शिक्षा खत्म होते ही पिता ने पास के कॉलेज में नामांकन करवा दिया। पिता चाहते थे कि बेटा सिवन पढ़ाई के साथ-साथ काम में भी हाथ बटाए।

पिता ने पास के कॉलेज में कराया दाखिला

अपने कॉलेज की पढ़ाई को लेकर सिवन ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा, जब मैं स्कूल से पास हुआ तो मेरे पिता ने मेरा दाखिला पास के कॉलेज में करवा दिया। उनका सोचना था कि मैं पास के कॉलेज में पढ़ाई करुंगा और पिता के साथ खेती में सहयोग करुंगा। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. मेधावी सिवन ने ग्रेजुएशन में गणित की परीक्षा न सिर्फ पास की, बल्कि 100 प्रतिशत अंक भी हासिल किए, जिसके बाद उनके पिता की सोच बदल गई और आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला एमआईटी में करवाया गया।

सफलता सिवन के इंतजार में पलकें बिछाए इंतजार कर रही थी. मेधावी छात्र सिवन ने साल 1980 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनलॉजी (एमआईटी) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली।

सफलता कर रही थी सिवन का इंतजार

1982 में इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले सिवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार बुलंदियों की ओर बढ़ते गए। या यूं कहें कि बुलंदियां सिवन की ओर खींची चली आ रही थी। उन्होंने साल 2006 में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की।

साल 1982 में ही सिवन ने इसरो ज्वाइन कर लिया और रॉकेट प्रोग्राम पर काम करने में जुट गए। इसरो के चेयरमैन बनने से पहले (साल 2018) वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक भी रहे। यह सेंटर रॉकेट का निर्माण करता है।

रॉकेट मैन के नाम से बुलाते हैं सहयोगी

क्रायोजॉनिक इंजन, पीएसएलवी, जीएसएलवी और री-यूज़ेबल लॉन्च व्हिकल्स (आरएलवी) का निर्माण करने में इन्होंने अहम योगदान दिया। इस कारण इन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाने लगा।

सिवन ने एक साथ 104 सेटेलाइट को लॉन्च करने में भी अहम भूमिका निभाई थी. यह लॉन्चिंग 15 फरवरी 2017 को हुई थी. एक साथ 104 सेटेलाइट को लॉन्च कर भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था.

ऐसा नहीं है कि सिवन ने चंद्रयान तक की दूरी को आसानी से छू लिया हो. इन दूरियों को तय करने में उन्हें काफी परेशानियों का समाना करना पड़ा. राह में न जाने कितनी बाधाएं आईं और सिवन के हौसले ने इन सभी बाधाओं को पस्त कर दिया।

गरीबी में बीता बचपन

अंग्रेजी अखबार के साथ एक ऐसी ही कहानी साझा करते हैं इसरो प्रमुख सिवन बातचीत के दौरान सिवन बताते हैं कि उनका बचपन मुफलिसी में गुजरा। स्कूल के दिनों में उनके पैरों में चप्पल या जूता नहीं होता था। उन्होंने बताया कि वह कॉलेज के दिनों तक धोती पहन कर पढ़ने जाया करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार तब पैंट पहनी थी, जब मैंने एमआईटी में दाखिला लिया था।

अपनी पसंद की मूवी पर बात करते हुए सिवन ने कहा कि उन्हें राजेश खन्ना की फिल्म आराधना बहुत पंसद है। इसरो चीफ ने बताया कि वह क्लासिकल गाने सुनते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने यह बताया कि उन्हें बागवानी का भी शौक है।